Fraudulent cotton export to Japan

424. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drown to a news-item in 'Vyapar' published from Bombay dated the 5th April, 1989 on the reported scandal by way of fraudulent cotton export to Japan;

(b) what is the quota fixed for export and how much has been exported so far and whether it is a fact that some of the exporting firms had no experience of cotton trade or export;

(c) whether it is also a fact that tenders were accepted at unimaginably high prices than the prevailing market prices in order to deliberately inflate export prices for turning black money into foreign exchange and also to take benefit of higher income tax exemption;

(d) whether the Textile Commissioner, Bombay is aware of this fraud since Japanese buyers are paying more for Indian cotton than for Pakistan's; and

(e) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Government have released an export quota of 101241 bales of Bengal Deshi cotton and one lakh bales of extra-long staple cotton to public agencies and private trade. A quantity of 850 bales of Bengal Deshi has been already exported. Since there is no bar to new entrants in the field of cotton exports, it is possible that some of the private parties may not have previous experience in this line.

(c) and (d) The revised export procedure involving *inter-se* allocation based on highest unit value realisation has resulted in extremely attractive price quotations and thus greater foreign exchange earnings to the country from such exports. Government are not aware of any fraud or malpractices in this regard.

(e) Does not arise.

स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा किये गये अघोषित धन का पता लगाने के लिए स्विटजरलैंड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

425. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1989 को भारत और स्विटजरलैण्ड द्वारा एक सहमति ज्ञापन (मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहमति ज्ञापन के अनुसार भारतीय अधिकारी आर्थिक अपराधों में अन्तर्ग्रस्त संदेहास्पद व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को वहां के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किये गये अवैध धन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां इस प्रकार का कितना धन जमा कराया गया है और वह किस-किस नाम से और कितना कितना है ?

वित्त संत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो केलेरियो) : (क) से (घ) पारस्परिकता और दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत के आधार पर आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल में परस्पर सहायता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, 20 फरवरी, 1989 को पत्रों का

अधीन प्रशासन करके स्विटजरलैंड सरकार के साथ एक समझौता किया गया है । इस समझौते की शर्तों के अनुसार, जांच पड़ताल वाले विशिष्ट मामलों के संबंध में सूचना/प्रमाण एकत्रित करने के लिए विधि प्रवर्तन अधिकरणों द्वारा स्विटजरलैण्ड के प्राधिकारियों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

स्विटजरलैण्ड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशियों के बारे में, इस समझौते के अंतर्गत, सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती ।

बड़े बांध

426. श्री राम जेठमलानी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान लूनो इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी के जल संसाधन इंजीनियरिंग विभाग के डाक्टर रोनी बैरनडट्सन द्वारा "बिग डैम्स नाट सूटेबल फार थर्ड वर्ल्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में देश में बड़े बांधों के स्थान पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना पर सक्रियता से विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) डाक्टर रोनी बेरनड्टन द्वारा दिए गए निष्कर्षों की ओर अभी सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि द्रवचालित (हाईड्रोलिक) संरचनाओं का आकार जल वैज्ञानिक, स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक स्थितियां, कृषकों की आवश्यकताएं, पर्यावरणिक विचार तथा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता जैसे उपयुक्तता के अनेक घटकों द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

Complaint from Tamil Nadu weavers Association regarding supply of yarn

427. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint from Tamil Nadu Weavers Association regarding the supply of yarn at unreasonable prices; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to supply adequate quantity of yarn at prices fixed by the Handloom Export Promotion Council?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) A memorandum from Tamil Nadu State Handloom Weavers Association, Salem, regarding sudden hike in the prices of yarn has been received.

(b) Government have taken a number of steps to ensure adequate supplies of yarn to handloom sector at reasonable prices such as the Hank Yarn Obligation Scheme, Loan assistance to the National Cooperative Development Corporation for setting up of Weavers' Cooperative Spinning Mills and expansion of capacity in the existing mills to build up captive production for the handloom sector, setting up of the National Handloom Development Corporation with the main aim of supplying yarn to the handloom sector. In order to safeguard the interests of the decentralised sector, certain corrective measures have also been taken to check the recent rising trend in yarn prices:—

(i) Import of cotton against expert of yarn on duty free REP/Advance licence basis has been permitted.

(ii) The export of bank yarn in count groups 1 to 60s is not being allowed.

(iii) Import of one lakh bale of medium/long staple cotton, duty free, for production of hank yarn for supply to